हुआ था वह बिहार प्रेस बिल के बारे में था लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के कागजों के बारे में लिख दिया ।

(iv) NEED FOR HUMAN BEHAVOUR WITH PRISONERS IN JAILS.

श्री मनीराम बांगड़ी (हिसार) : बन्दी बनाने के बाद सरकार और सभ्य सरकार की खासतौर से जिम्मेदारी है कि जेल में बन्दी के साथ मानवीय व्यवहार दिया जाए । जिस देश में चाहे सरकार विदेशी भी क्यों न हो बन्दियों के साथ गैर-मानवीय व्यवहार करती है वह मानवीय सरकार नहीं । आज आजाद भारत में रोजाना अखबारों में शिकायत जेल में लड़कों से यानी नबालिग बच्चों से बदचलनी दुर्व्यवहार कहीं जेल में आंख फोड़ने के कांड, कहीं राशन पूरा न देना, गंदी खुराक, सर्दी व गर्मी के मुताबिक वस्त्र न देना, दो आदमी की जगह दस आदमी घुसेड़ देना यहां तक कि औरतों के साथ जेल में बलात्कार के वाकये सामने आए । राजनीतिक बंदियों के साथ खासतौर से राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए । आजकल पंजाब के जेलें बंदियों से भरी हुई हैं, बल्कि जितनी तादाद उनमें होनी चाहिए उससे ज्यादा है ।

मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार उनके रहने की पूरी व्यवस्था करे, टेन्ट लगाए या अन्य प्रदेशों में भेजे । दवाई-दारू दे और भोजन का पूरा प्रबंध करे । इसके लिए मेरी राय है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय एक कमेटी बनाए जो जेल सुधार कमेटी हो और तमाम देश में घूम कर जेल के लिए जो सुविधाजनक जेल मैनुअल (जेल संहिता) बन सके, बनाए । किसी कौम की सभ्यता और अच्छापन की निशानी सबसे ज्यादा उसकी जेल से होती है क्योंकि उसमें देशी, स्वदेशी, विदेशी अच्छे और बुरे सभी किस्म के लोग होते हैं । यह भारत है । कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ । बाबा नानक जेल गए । छटे गुरू श्री हरगोविन्द ने ग्वालियर के किले में जेल काटी, बन्दी छुड़ाए । राष्ट्रपिता गांधी जेल को सुधारने में इतने तत्पर थे । अगर आज किसी जेल में आदमी को तकलीफ होती है तो गांधी की आत्मा को ।

(v) TAMIL NADU BANDH AGAINST CENTRAL GOVERNMENT FOR FAILURE TO SOLVE KAVERI WATER DISPUTE

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): It is learnt that a Bandh is being organized on 15th October, 1982 by the Tamil Nadu Government against the Central Government, alleging that the Central Government have failed to solve the Kaveri water problems. The said Bandh is purely politically motivated, and attempts to shift the burden on the Centre, without the State authorities taking any steps either to get water from Karnataka, or to solve the problems by taking initiative. In fact, the Central Government convened the Conferences of Chief Ministers of the Southern States to discuss the water supply from Kaveri, and the problems related thereto. But the State representatives and the C.M. did not attend these Conferences, as mentioned by the Agriculture Minister. For the past many months, the State Government have not taken any steps to get the water supply for Tamil Nadu. The result is that the entire Tamil Nadu is facing serious drought and famine situation. At the same time, charges and

[Shri K. Mayathevar]

allegations are being made against the Centre without any justification, by the Government of Tamil Nadu. The said Bandh by the Tamil Nadu Government is neither legal nor constitutional; and the Central Government should declare the said Bandh unlawful, unconstitutional, unwarranted, unnecessary and undemocratic.

(vi) LOAN TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FROM BANKS FOR BUYING MILCH CATTLE.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : विभिन्न बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए भैंस, गाय एवं अन्य जानवरों को खरीदने के लिए सरकार के आदेशानुसार ऋण। सहायता का प्रावधान है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को जीवन स्तर ऊंचा उठ सके । लेकिन खेद है कि यह सहायता सिर्फ कागज पर ही है । गरीब हरिजन आदिवासी महीनों बैंक का चक्कर काट कर थक जाते हैं । लेकिन उन्हें एक पैसा नहीं मिलता । पैसा उन्हीं को मिलता है जो उन्हें खुश करते हैं । बिहार में स्थिति और खराब है । बिहार में बैंक के मैनेजर द्वारा खुलमखुल्ला नाजायज पैसा मांगा जाता है । इसको लेकर गरीबों में काफी क्षोभ है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों में कितने हरिजन एवं आदिवासी को कुल कितनी राशि जानवर के खरीद हेतु ऋण या सहायता के रूप में दी गई । सरकार से यह भी आग्रह है कि ऐसा नियम बनावें जिससे गरीबों को आसानी से सहायता राशि या ऋण उपलब्ध हो सके ।

(vii) MERGER OF COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION WITH COAL INDIA LTD.

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarma): The Coal Welfare Organisation financed out of the cess on despatches of coal and C.M.L.W. Fund Act, 1947 has been providing medical, housing and other welfare measures for coal mines in the country for the last four decades. Majority of the 4000 employees of the Fund who are Central Government Servants with pensionable status have rendered over 15—20 years service.

In March, 1981, two Regional Hospitals of the Fund at Naisarai and Phusro were transferred to C.I.L. Recently a decision is stated to have been taken to transfer 12 more Regional Hospitals to C.I.L. Unfortunately, in spite of repeated representation by this Association the matter regarding protection of seniority, rank and prior settlement of the employees pension, gratuity and other dues of the employees, has remained undecided till now. The Association's demand for full merger of CMLWO into CIL instead of piecemeal transfer has also been ignored.

Having been utterly distressed the employees of the CMLWO have been staging mass rally, dharna and relay fast since 13-9-1982 against the unilateral decision of piecemeal transfer of RHS to CIL and demanding full merger with prior settlemnt of terms and conditions.

It is, therefore. urged upon the Energy Minister to kindly proclaim at the earliest that the merger will be complete and not carried out in instalments to enable those sitting in relay fast to break their fast easing tension and labour unrest and resume their work in the interest of the nation.